गोरखपुर से प्रकाशित

RNI Reg. NO. UPBIL/2023/87841

साप्ताहिक

स्वदेशी इनक्रेडिबल

Web:www.sinews.in/E-mail: info@sinews.in

सिर्फ सच के साथ...

वर्ष : 02 अंक : 10 गोरखपुर रविवार 25 अगस्त 2024 पृष्ठ : 8 मूल्य 02 रूपया

नेपाल में 40 यात्रियों को लेकर जा रही भारत की नंबर प्लेट वाली बस नदी में गिरी, अब तक 18 की मौत

काठमांडू । इस बीच उत्तर प्रदेश राहत आयुक्त ने कहा कि नेपाल की घटना के संबंध में हम यह पता लगाने के लिए संपर्क स्थापित कर रहे हैं कि क्या बस में उत्तर प्रदेश का कोई व्यक्ति था। घटना के बारे में विस्तृत जानकारी की प्रतीक्षा है।मध्य नेपाल में शुक्रवार को एक भारतीय यात्री बस के मर्सियांगडी नदी में गिर जाने से कम से कम 18 लोगों की मौत हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक, बस में 40 यात्री सवार थे। इस तरह चालक, सहचालक और कंडक्टर को मिलाकर बस में कुल 43 लोग थे। सभी यात्री महाराष्ट्र के बताए जा रहे हैं। बस ने 8 दिन के परमिट के साथ 20 अगस्त को रूपन्देही के बेलहिया चेक–पॉइंट (गोरखपुर) से नेपाल में प्रवेश किया था। दुर्घटना तनहुन जिले के आइना पहाड़ा में हुई।

सशस्त्र पुलिस बल नेपाल आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण विद्यालय के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) माधव पौडेल के नेतृत्व में 45 कर्मियों की एक टीम दुर्घटनास्थल पर पहुंच चुकी है। बचाव अभियान शुरू किया जा चुका है। प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार, लगभग 18 शव बरामद किए गए हैं। 17 को सुरक्षित बचा लिया गया है। आठ लोग अब भी लापता हैं।

जानकारी के मुताबिक, गोरखपुर से यात्रियों को लेकर नेपाल गई एक भारतीय बस शुक्रवार को हादसे का शिकार हो गई। बस पोखरा से काठमांडू जा रही थी। तनहुन के एसपी बीरेंद्र शाही ने हादसे की जानकारी दी है। स्थानीय पुलिस कार्यालय के निरीक्षक अबू खैरेनी मौके पर मौजूद हैं। सेना और सशस्त्र बलों को सूचित कर दिया गया है।

बस का नंबर यूपी 53 एफटी 7623 बताया जा रहा है। आगे की जानकारी का इंतजार है।इस बीच उत्तर प्रदेश राहत आयुक्त ने कहा कि नेपाल की घटना के संबंध में हम यह पता लगाने के लिए संपर्क स्थापित कर रहे हैं कि क्या बस में उत्तर प्रदेश का कोई व्यक्ति था। घटना के बारे में विस्तृत जानकारी की प्रतीक्षा है।

जम्मू कश्मीर का अलग झंडा, अलग संविधान, क्या कांग्रेस की भी है यही मंशाय एनसी से गठबंधन के बाद अमित शाह के राहुल गांधी से 10 सवाल

श्रीनगर। जम्मू–कश्मीर विधानसभा चुनाव का एलान हो गया है। इस बार तीन चरणों में मतदान होगा। वोटों की गिनती चार अक्टूबर को होगी।

चुनावी बिगुल बजने के बाद कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) के साथ गठबंधन किया है। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे के जम्मू–कश्मीर दौरे के दौरान गठबंधन को अंतिम रूप दिया गया।केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन पर 10 तीखे सवाल किए हैं। उन्होंने कहा कि सत्ता के लालच में कांग्रेस देश की एकता और सुरक्षा को बार–बार खतरे में डाल रही है।

कांग्रेस ने जम्मू–कश्मीर चुनाव में अब्दुल्ला परिवार की श्नेशनल कॉन्फ्रेंसश के साथ गठबंधन करके एक बार फिर अपने गुप्त इरादों को उजागर कर दिया है। इस गठबंधन पर अमित शाह ने कांग्रेस और राहुल गांधी से 10 तीखे सवाल पूछे हैं।

अमित शाह के 10 तीखे सवाल

क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू–कश्मीर के लिए अलग झंडे के वादे का समर्थन करती है कांग्रेस?

क्या राहुल गांधी और कांग्रेस अनुच्छेद 370 और 35ए को फिर से बहाल करने और जम्मू–कश्मीर को अशांति और आतंकवाद के युग में वापस धकेलने के एनसी के फैसले का समर्थन करती है?

क्या कांग्रेस कश्मीर के युवाओं के बजाय पाकिस्तान के साथ बातचीत करके फिर से अलगाववाद को बढ़ावा देने का समर्थन करती है?

क्या कांग्रेस और राहुल गांधी पाकिस्तान के साथ श्एलओसी व्यापारश शुरू करने के नेशनल कॉन्फ्रेंस के फैसले का समर्थन करती है, जिससे सीमा पार आतंकवाद और उसके पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा मिलता है?

क्या कांग्रेस आतंकवाद और पथराव में शामिल लोगों के रिश्तेदारों को सरकारी नौकरियों में बहाल करने का समर्थन करती है, जिससे आतंकवाद और उग्रवाद का युग वापस आ जाएगा?

गठबंधन ने कांग्रेस पार्टी के आरक्षण विरोधी रुख को उजागर कर दिया है। क्या कांग्रेस दलितों, गुज्जरों, बकरवालों और पहाड़ी समुदायों के लिए आरक्षण समाप्त करने का समर्थन करती है?

क्या कांग्रेस चाहती है कि श्शंकराचार्य हिलश को श्तख्त–ए–सुलेमानश और श्हरि हिलश को श्कोह–ए–मारनश के नाम से जाना जाए?

क्या कांग्रेस जम्मू–कश्मीर की अर्थव्यवस्था को फिर से भ्रष्टाचार में धकेलने और चुनिंदा पाकिस्तान समर्थित परिवारों को सौंपने की राजनीति का समर्थन करती है?

क्या कांग्रेस पार्टी एनसी की जम्मू और घाटी के बीच भेदभाव की राजनीति का समर्थन करती है?

क्या कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी कश्मीर को स्वायत्तता देने की जेकेएनसी की विभाजनकारी राजनीति का समर्थन करते हैं?

यूक्रेन में बोले पीएम मोदी- संघर्ष बच्चों के लिए विनाशकारी

कीव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों यूरोप में हैं। वह 21 और 22 अगस्त को दो दिवसीय पोलैंड यात्रा पर राजधानी वारसॉ में थे। इसके बाद पीएम मोदी ट्रेन से युद्धग्रस्त यूक्रेन पहुंचे। अपनी इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के साथ वार्ता करेंगे। इसमें यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान पर भी चर्चा होगी।

भारत–यूक्रेन के बीच चार समझौतों पर हुए हस्ताक्षरपीएम मोदी के कीव दौरे के दौरान भारत–यूक्रेन के बीच चार समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने बैठक की।

इसमें सांस्कृतिक क्षेत्र में सहयोग, स्वास्थ्य क्षेत्र, कृषि क्षेत्र में सहयोग और मानवीय मदद को लेकर समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।

रूस–यूक्रेन संघर्ष बच्चों के लिए विनाशकारीरू मोदी

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की से मुलाकात के बाद मोदी ने एक्स पर ट्वीट किया। पीएम ने लिखा कि मैनें और राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने कीव में यूक्रेन नेशनल म्यूजियम में युद्ध में मारे गए बच्चों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने लिखा कि रूस–यूक्रेन संघर्ष विशेष रूप से बच्चों के लिए विनाशकारी है। इस संघर्ष में जान गंवाने वाले बच्चों के परिवारों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि उन्हें इस दुख को सहने की ताकत मिले।

रेलवे में ठेकेदार की अपहरण के बाद हत्या, आरोपी गिरफ्तार

नोएडा। उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर की थाना बीटा–दो पुलिस ने रेलवे में एक ठेकेदार को अगवा कर उसकी हत्या करने के आरोप में शुक्रवार को एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।पुलिस उपायुक्त (जोन द्वितीय) साद मियां खान ने बताया कि थाना बीटा–दो क्षेत्र की एक सोसाइटी में रहने वाले अंकुश (40) नौ अगस्त की रात से लापता थे। खान ने बताया कि उनके परिजन ने इस मामले में थाना बीटा–दो में मुकदमा दर्ज कराया था और घटना की रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच कर रही पुलिस ने सर्विलांस के माध्यम से तथा गोपनीय जानकारी के आधार पर प्रवीन नामक व्यक्ति को हिरासत में लिया।

उन्होंने बताया कि पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया कि उसने अंकुश की हत्या कर शव थाना नॉलेज पार्क क्षेत्र में स्थित एक जंगल में फेंक दिया है। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर शव बरामद कर लिया है और हत्या में प्रयुक्त हथौड़ा और कार आदि भी बरामद कर ली है।पूछताछ के दौरान पुलिस को पता चला है कि आरोपी और अंकुश के बीच एक फ्लैट की खरीद को लेकर विवाद था। यह फ्लैट अंकुश का था और आरोपी उसे खरीदना चाहता था। उन्होंने बताया कि आरोपी को अदालत में पेश किया जा रहा है।

बीएचयू में 11 दिन की हड़ताल, बिना इलाज लौटे 35 हजार मरीज, 1000 लोगों की नहीं हुई सर्जरी

वाराणसी। कोलकाता कांड को लेकर बीएचयू अस्पताल में 11 दिन रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर रहे। 11 दिन में से नौ दिन ओपीडी चली, लेकिन 35 हजार मरीज बिना इलाज के लौटे।

11 दिन की हड़ताल में नौ दिन ओपीडी चली और इन नौ दिनों में ओपीडी में बिना इलाज करीब 35 हजार मरीजों को लौटना पड़ा। जबकि एक हजार मरीजों की सर्जरी नहीं हुई। 440 मरीजों की ही भर्ती हो सकी जबकि 672 को डिस्चार्ज किया गया। आईएमएस बीएचयू के रेजिडेंट 13 अगस्त से ही ओपीडी, वार्ड, जांच केंद्र सहित अन्य जगहों पर कामकाज ठप कर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने इमरजेंसी सेवाओं में सहयोग की बात कही थी, लेकिन कुछ दिनों से इमरजेंसी में भी रेजिडेंट नहीं नजर आए।

ओपीडी में सामान्य दिनों में बीएचयू में करीब छह हजार मरीज आते हैं।

इसमें चार हजार नए जबकि दो हजार फॉलोअप के मरीज आते हैं। 150 सर्जरी और रेडियोलॉजी में 1000 जांच रोज होती है। हड़ताल की वजह से पहले दिन 4019 मरीज देखे गए, इसके बाद संख्या घटती गई। 17 अगस्त को 151, 19 अगस्त को 651 मरीज तक संख्या आ गई।

इमरजेंसी, आईसीयू में पहुंचे, ओपीडी में आज से सेवाएंआईएमएस बीएचयू के रेजिडेंट शनिवार से ओपीडी में सेवाएं देंगे। निदेशक प्रो. एसएन संखवार ने बताया कि कि रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन की ओर से हड़ताल खत्म करने की सूचना मिल गई है। शुक्रवार देर शाम से आईसीयू, इमरजेंसी, ट्रॉमा सेंटर सहित अन्य इमरजेंसी, सेवाओं में रेजिडेंट लग गए हैं। सामान्य दिनों की तरह वह शनिवार सुबह से ओपीडी, जांच केंद्र,वार्ड सहित अन्य जगहों पर अपनी सेवाएं देंगे।

किस दिन आए कितने मरीज

तारीख	ओपीडी जांच	सर्जरी भर्ती	रेडियोलॉजी डिस्चार्ज	
13 अगस्त	4019	47	174	64
14 अगस्त	2300	41	187	44
16 अगस्त	3469	25	219	51
17 अगस्त	159	15	56	32
19 अगस्त	631	8	50	29
20 अगस्त	2395	34	118	66
21 अगस्त	2220	27	133	39
22 अगस्त	3067	34	161	53
23 अगस्त	2478	45	276	62

ट्रॉमा सेंटर में भी नहीं दिखा सके 3000 से अधिक लोग

बीएचयू ट्रॉमा सेंटर की ओपीडी में भी औसतन करीब 500 लोग सामान्य दिनों में आते हैं। रेजिडेंट की हड़ताल की वजह से दूर दराज से आने वाले मरीजों को यहां कंसल्टेंट ने देखा। हड़ताल के दिनों में भी यहां हर दिन 100 से 150 मरीज देखे गए। हड़ताल में नौ दिन चली ओपीडी में करीब 3000 से अधिक मरीज डॉक्टर को नहीं दिखा सके।

मासूम बच्चियों को कमरे में बंद कर नकली सांप से डराया, फिर किया घिनौना काम

मुरादाबाद। मुरादाबाद से हैरान करने वाली खबर सामने आई है। यहां एक युवक ने दो मासूम बच्चियों को कमरे में बंद कर लिया। इसके बाद उन्हें नकली सांप से डराया और फिर दुष्कर्म का प्रयास किया।

मुरादाबाद के एक मोहल्ले में शुक्रवार शाम साढ़े सात बजे दो बच्चियों को एक युवक ने कमरे में बंद कर उनके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। आरोपी ने उन्हें नकली सांप से डराया। एक बच्ची भागकर बाहर आ गई और शोर मचा दिया। इसके बाद मासूमों के परिजन और अन्य लोग आ गए। उन्होंने आरोपी को पकड़ लिया और दूसरी बच्ची को छुड़ाया। आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया गया। अगवानपुर के एक मोहल्ला निवासी महिला ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसकी आठ वर्षीय बेटी कक्षा तीन में पढ़ती है। शुक्रवार की शाम करीब साढ़े सात बजे वह छह वर्षीय फुफेरी बहन के साथ बाजार से समोसा लेने गई थी।

बाजार में एक युवक बच्चियों को बिस्कुट देने का लालच देकर अपने साथ ले गया। बच्चियों को ले जाकर आरोपी ने उन्हें कमरे में बंद कर दिया और दोनों के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। आरोपी ने बच्चियों को खिलौले वाले सांप से डराया। शोर मचाने पर बच्चियों की पिटाई कर दी। इसके बाद आरोपी ने आठ वर्षीय बच्ची को कमरे में बंद करके बाहर से ताला लगा दिया। वहीं घर का गेट बंद करके दूसरी बच्ची को आंगन में खड़ा कर दिया और वह मकान की छत पर चला गया।

काफी देर तक आंगन में खड़ी बच्ची किसी तरह घर से निकलकर बाजार में पहुंच गई। बाजार में उसको ममेरी बहन मिल गई। किशोरी पहले से उसको बाजार में तलाश रही थी। उसने अपनी बहन को घटना के बारे में बताया। किशोरी बाजार से दो युवकों को साथ में लेकर मकान पर पहुंची। उन्होंने मकान का ताला तोड़कर बच्ची को बाहर निकाल। इसके बाद आरोपी को पकड़ लिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी रामपुर के एक गांव का रहने वाला है। एक साल से किराये के मकान में रहता था। यहां वह बिस्कुट बेचने का काम करता था। सीओ सिविल लाइंस अर्पित कपूर ने बताया जांच कर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जाएंगी।

कन्हैया को सजाने-संवारने को बाजार में आईं पोशाकें, मुकुट और बांसुरी से सजी दुकानें

शाहजहाँपुर। शाहजहांपुर में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी को लेकर बाजार सजने लगे हैं। बाजार में तरह तरह पोशाकें आईं हैं। अष्टधातु से बने वस्त्रों की कीमत 3100 से 5100 रुपये तक है। चांदी के पालने भी बिक रहे हैं।

श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का पर्व 26 अगस्त को मनाया जाएगा। इसको लेकर घरों व मंदिरों में तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। शाहजहांपुर के बाजार में भगवान श्रीकृष्ण के बाल स्वरूप को सजाने–संवारने के लिए सुंदर पोशाकें, चांदी के पालने, मुकुट तथा बांसुरी आदि बाजार में आ चुकी हैं। जिसकी दुकानें सजने लगी हैं।

शहर के सदर बाजार, बहादुरगंज, चौक तथा जलालनगर स्थित बाजारों में सजावटी व पूजन सामग्री की बड़ी दुकानें स्थित हैं। इनके साथ ही सड़क के किनारे छोटी–छोटी दुकानें लग रही हैं। जिन पर भगवान श्रीकृष्ण जन्मोत्सव को लेकर पोशाक समेत शृंगार सामग्री उपलब्ध है।

पोशाकों की कीमत

दुकानदारों के मुताबिक, लड्डू गोपाल के वस्त्र 10 रुपये लेकर 2000 रुपये तक उपलब्ध हैं।

यूपी डीजीपी ने दिए निर्देश, जन्माष्टमी और चेहल्लुम को देखते हुए करें विशेष तैयारी

लखनऊ। यूपी डीजीपी ने जन्माष्टमी पर्व के दौरान पुख्ता सुरक्षा इंतजाम करने के निर्देश दिए। उन्होंने जन्माष्टमी में शोभा यात्रा जुलूसों में पर्याप्त पुलिस प्रबंध करने के लिए कहा है। डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा कि जन्माष्टमी तथा चेहल्लुम के कार्यक्रम जिन स्थानों पर एक साथ आयोजित हों, वहां अलग से योजनाबद्ध तैयारी की जाए। दोनों के आयोजकों से स्थानीय मजिस्ट्रेट के साथ वार्ता की जाए। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा स्वयं पुलिस प्रबंध कराए जाएं। शोभायात्रा जुलूसों में सुरक्षा के लिए पर्याप्त पुलिस प्रबंध करें और वीडियोग्राफी कराई जाए। महत्वपूर्ण संवेदनशील स्थलों पर ड्रोन कैमरों से भी चेकिंग करायी जाये। डीजीपी शुक्रवार को जन्माष्टमी समेत आगामी त्योहारों के दृष्टिगत एडीजी यातायात, रेलवे, जोन, आईजी रेंज और जिलों के पुलिस कप्तानों को दिशा–निर्देश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि त्योहारों पर किसी नई परंपरा की अनुमति नहीं दी जाए। असामाजिक, अवांछनीय तत्वों की सूचियों को अपडेट करके निरोधात्मक कार्यवाही की जाए। जन्माष्टमी से संबधित समस्त आयोजन, लीला स्थल, पंडाल, मंदिर एवं जुलूसों को सूचीबद्ध कर पुलिस की तैनाती करें। जन्माष्टमी में जिन स्थानों पर बीते वर्षों में विवाद हुआ हो, वहां उसे सुलझाने तथा संवेदनशीलता को दूर करने की कार्यवाही करें।

प्रत्येक छोटी से छोटी घटना को गंभीरता से लेकर प्रभावी उपाय किए जाएं। भीड़ प्रबंधन एवं भीड़ नियंत्रण के लिए पहले से प्लानिंग एवं तकनीक का प्रयोग कर इंतजाम किए जाएं। सोशल मीडिया की राउंड द क्लॉक मॉनिटरिंग करें। भ्रामक एवं आपत्तिजनक पोस्ट का तत्काल खंडन किया जाए।

पुलिस भर्ती परीक्षा में ब्लूटूथ से नकल करते पकड़ा गया युवक

रायबरेली। जिले में पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर चाक चौबंद व्यवस्था का दावा किया गया था, लेकिन एक मुन्ना भाई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ परीक्षा केंद्र में प्रवेश होने में सफल हो गया। मोबाइल को ब्लूटूथ से जोड़कर बड़े इत्मीनान से नकल कर रहा था। लेकिन परीक्षा खत्म होने से महज आधा घंटे पहले कक्ष निरीक्षकों की नजर उसपर पड़ गई। जिसके बाद नकलची को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस पूछताछ कर रही है। साथ ही और कौन लोग इसमें शामिल हैं, इसकी भी जांच की जा रही है। आचार्य द्विवेदी इंटर कॉलेज को भी जिले में परीक्षा के लिए केंद्र बनाया गया था। शुक्रवार को औरैया जिले के बेला थाना क्षेत्र के पुरवा ताला निवासी उपेंद्र सिंह कक्ष संख्या 13 में मोबाइल से ब्लूटूथ डिवाइस को कनेक्ट कर नकल कर रहा था।

एएमयू के बाहर फायरिंग, रिक्शा चालक को लगी गोली, मेडिकल में भर्ती, तीन संदिग्ध हिरासत में

अलीगढ़। दो गुटों में विवाद के दौरान मारपीट हो गई। इस बीच गोल मार्केट जमालपुर के रिक्शा चालक शेर खान वहां से गुजर रहे थे। बीच–बचाव कराने के दौरान किसी एक पक्ष की ओर से तमंचे से फायर किया गया, गोली शेर खान को लगी और वह वहीं पर गिर पड़े।

एएमयू के सेंचुरी गेट के पास पुरानी चुंगी पर 23 अगस्त शाम दो गुटों में मारपीट के दौरान फायरिंग हो गई। एक गोली रिक्शा चालक के कमर के पास लगी। इसके बाद दोनों गुटों के हमलावर भाग निकले, जिनमें से कुछ की पहचान प्लस टू के छात्रों के रूप में हुई है, जिनमें से तीन को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। घायल को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। बताया गया है कि पुरानी चुंगी के किला रोड पर दो गुटों में विवाद के दौरान मारपीट हो गई। इस बीच गोल मार्केट जमालपुर के रिक्शा चालक शेर खान वहां से गुजर रहे थे। बीच–बचाव कराने के दौरान किसी एक पक्ष की ओर से तमंचे से फायर किया गया, गोली शेर खान को लगी और वह वहीं पर गिर पड़े । यह देख दोनों गुट वहां से कैंपस में अल्लाम इकबाल हॉल की ओर भाग गए।

इस सूचना पर पुलिस आ गई। घायल को मेडिकल कॉलेज भेजने के साथ घटना स्थल के आसपास व कैंपस के सीसीटीवी देखे गए। जिसमें प्लस टू के तीन छात्र पहचाने गए। प्रॉक्टर कार्यालय के अनुसार पुलिस का सहयोग किया जा रहा है। वहीं एएसपी अमृत जैन के अनुसार जांच की जा रही है। तीन संदिग्ध हिरासत में लिए गए हैं।

कबाड़ से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर घर में घुसा, हादसे में खलासी की मौत, चालक घायल

आजमगढ़। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में एक ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे एक घर में घुस गया। इस दौरान ट्रक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में खलासी की मौत हो गई। जबकि चालक घायल हो गया। आजमगढ़ जिले में शुक्रवार की देर रात बड़ा हादसा हुआ।

जौनपुर की तरफ जा रहा ट्रक बरदह थाना क्षेत्र के छांगुरराम राजेपुर गांव के पास अनियंत्रित होकर एक घर में घुस गया। घटना में ट्रक के खलासी की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घायल ट्रक चालक को उपचार के लिए मंडलीय जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। चंडीगढ़ के मोहाली का रहने वाल सुरेंद्र कुमार (42) ट्रक चालक है। वह चंडीगढ़ से कबाड़ लेने के लिए मऊ जनपद आया हुआ था। साथ ही उसका खलासी शिवदयाल (40) भी था। शुक्रवार की रात को वे मऊ से कबाड़ लादकर हिमाचल जा रहे थे। देर रात लगभग एक बजे जैसे ही ट्रक बरदह थाना क्षेत्र के छांगुरराम राजेपुर गांव के समीप पहुंचा। अचानक ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे स्थित एक घर में घुस गया। जिससे ट्रक बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं ट्रक में बैठे खलासी शिवदयाल की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि ट्रक चालक सुरेंद्र कुमार का पैर टूट गया। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और ट्रक चालक को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया।

देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ, 'मूड ऑफ द नेशन' सर्वे में बने देश में नंबर वन

लखनऊ। 30 राज्यों की जनता से सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री के बारे में पूछे गये सवालों में योगी आदित्यनाथ को सर्वाधिक मत मिले हैं। जनता से पूछा गया कि वो किसे देश का सबसे बेहतरीन मुख्यमंत्री मानते हैं, इसपर 33 प्रतिशत से अधिक लोगों ने योगी आदित्यनाथ के नाम पर अपनी मुहर लगाई है। बीते सात साल से उत्तर प्रदेश की कमान संभाल रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फिर देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री बनकर उभरे हैं। प्रतिष्ठित मीडिया समूह के श्मूड ऑफ द नेशनश सर्वे में योगी को नंबर वन सीएम के तौर पर जनता ने चुना है। देशभर में 1.36 लाख से अधिक जनता के बीच हुए सर्वे में 33 प्रतिशत से अधिक लोगों ने योगी को बेस्ट सीएम माना है। योगी इस सर्वे में लगातार तीसरी बार देश के बेस्ट चीफ मिनिस्टर चुने गये हैं। वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बहुत पीछे हैं।

मूड ऑफ द नेशनश सर्वे में देश के 30 राज्यों की जनता से सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री के बारे में पूछे गये सवालों में योगी आदित्यनाथ को सर्वाधिक मत मिले हैं। जनता से पूछा गया कि वो किसे देश का सबसे बेहतरीन मुख्यमंत्री मानते हैं, इसपर 33 प्रतिशत से अधिक लोगों ने योगी आदित्यनाथ के नाम पर अपनी मुहर लगाई है। इस सर्वे में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मात्र 13.8 प्रतिशत लोगों ने लोकप्रिय माना है, जबकि पश्चिम बंगाल की सीएम लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं। उन्हें 9.1 प्रतिशत लोगों ने समर्थन दिया। वहीं चौथे नंबर पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन हैं, जिन्हें 4.7 प्रतिशत मत मिला। इसी तरह पांचवें नंबर पर आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू हैं, जिन्हें 4.6 फीसदी लोगों ने समर्थन दिया। इस लिस्ट में महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, कर्नाटक के सीएम सिद्दारमैया, असम के हिमंता बिस्वा सरमा, उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी कुछ हद तक समर्थन मिला है। दावा किया जाता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते साढ़े सात साल में कानून–व्यवस्था से लेकर रोड कनेक्टिविटी, बिजली, स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में मिशन मोड में कार्य किया। इसके साथ ही यूपी को उद्योग प्रदेश बनाने में जुटे योगी ने यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के जरिए 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त करके नया कीर्तिमान रचा है।इसके अलावा रोजगार को लेकर भी दावे किए जाते हैं। योगी सरकार की तरफ से दावा किया जाता है कि दो करोड़ युवाओं को रोजगार और साढ़े छह लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है। इससे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता में इजाफा हुआ है।

हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर प्रदर्शन : कांग्रेस के मौजूदा व पूर्व प्रदेश अध्यक्ष समेत 273 समर्थकों पर केस दर्ज

लखनऊ। हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर प्रवर्तन निदेशालय के कार्यालयों पर प्रदर्शन करने जा रहे कांग्रेस नेता व कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। उनके खिलाफ हजरतगंज और गौतमपल्ली थाने में शिकायत हुई थी। ईडी कार्यालय पर बृहस्पतिवार को प्रदर्शन करने जा रहे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सहित सौ लोगों के खिलाफ हजरतगंज थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। चौकी इंचार्ज ने इनके खिलाफ थाने में शिकायत की है। इसके अलावा गौतमपल्ली थाने में 23 नामजद और 150 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।

चौकी इंचार्ज हजरतगंज राहुल कुमार सिंह के मुताबिक कांग्रेस पार्टी कार्यालय से प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में बृहस्पतिवार को समर्थक हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर ईडी कार्यालय पर प्रदर्शन करने जा रहे थे। जबकि शहर में निषेधाज्ञा लागू है। राजभवन गेट नंबर दो के पास जब पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने का प्रयास किया तो प्रदेश अध्यक्ष व समर्थक हंगामा करने लगे।इस पर हजरतगंज थाने में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राज, पूर्व अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, सांसद तनुज पूनिया, राष्ट्रीय महासचिव धीरज गुर्जर, कोषाध्यक्ष शिव पांडेय, पूर्व विधायक अखिलेश प्रताप सिंह, सेवादल प्रदेश अध्यक्ष प्रमोद पांडेय, एनएसयूआई के अनस रहमान, प्रशासन प्रभारी दिनेश सिंह, संगठन सचिव अनिल यादव, पूर्व नगर अध्यक्ष मुकेश सिंह चौहान, युवा कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष अंकित तिवारी, सेवा दल मध्य के पूर्व अध्यक्ष राजेश काली, अध्यक्ष दक्षिणी डॉ. शहजाद आलम और अमित के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।गौतमपल्ली थाने में भी केस दर्ज

गौतमपल्ली थाने के गुलिस्तां चौकी प्रभारी रमेश चंद्र पांडेय ने भी प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, पूर्व अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, जिलाध्यक्ष वेद प्रकाश, उपाध्यक्ष प्रशासन दिनेश कुमार सिंह, प्रदेश मंडल नावेद नकवी, नितांत सिंह उर्फ नितिन, रुद्रदमन सिंह बबलू, शहर अध्यक्ष अमित श्रीवास्तव, डॉ. शहजाद आलम, चेयरमैन ओबीसी मनोज यादव, प्रदेश अध्यक्ष यूथ कांग्रेस अंकित तिवारी, प्रदेश अध्यक्ष एनएसयू अनस अहमद, कोषाध्यक्ष उत्तर प्रदेश कांग्रेस शिव पांडेय, प्रवक्ता संजय दीक्षित, प्रवक्ता संजय सिंह, लल्लन कुमार, बल्देव सिंह लाटी, प्रदेश अध्यक्ष महिला कांग्रेस ममता चौधरी, पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश मोहित अहमद, पूर्व कैबिनेट मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दकी, एनएसयूआई के महासचिव आरएन मिश्र, ओबीसी मोर्चा के विनोद यादव, दीप रैकवार व 150 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज कराया है।

सम्पादकीय

महिलाओं की सुरक्षा और समाज

कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में प्रशिक्षु महिला चिकित्सक की यौन हिंसा के बाद हुई हत्या ने एक बार फिर साबित किया है कि देश में कामकाजी महिलाओं के लिये कार्यस्थल पर परिस्थितियां कितनी असुरक्षित हैं। वह भी इतनी भयावह कि कार्यस्थल पर ही प्रशिक्षु महिला चिकित्सक के साथ यह सब वीभत्स घट जाता है। निश्चित रूप से कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न मानव अधिकारों का सरासर उल्लंघन ही है। कार्यस्थल पर महिलाओं के लिये सुरक्षा अनुकूल वातावरण बनाने के मद्देनजर विशाखा दिशा–निर्देश जारी करने के सत्ताईस साल बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को डॉक्टरों की सुरक्षा को संस्थागत बनाने के लिये तुरंत कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। वहीं दूसरी ओर देश की सर्वोच्च अदालत के निर्देश के अनुपालन हेतु गठित एक राष्ट्रीय टास्क फोर्स को चिकित्सा पेशवरों की सुरक्षा, महिला चिकित्सकों के लिये अनुकूल कामकाजी परिस्थितियां बनाने तथा उनके हितों की रक्षा के लिये प्रभावी सिफारिशें तैयार करने का काम सौंपा गया है। विश्वास किया जाना चाहिए कि ये सिफारिशें यदि जमीनी स्तर पर भी प्रभावी साबित हुईं तो किसी भी पेशे में कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा के लिये असरकारी साबित होंगी। लेकिन यह तभी संभव है जब सभी हितधारक एक स्तर पर एकजुट होकर इस दिशा में काम करेंगे। निस्संदेह, किसी भी दुर्भाग्यपूर्ण घटना होने के वक्त तमाम तरह के उपक्रम होते हैं, लेकिन कुछ समय बाद सब कुछ ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। यही वजह है कि नई कार्ययोजना बनाते समय इस बात का आकलन करने की सख्त जरूरत महसूस की जा रही है कि महिला सुरक्षा को लेकर मौजूदा कानून और दिशा–निर्देश जमीनी स्तर पर बदलाव लाने में कितने सफल रहे हैं। सही मायनों में कानून बनाने और दिशा–निर्देश जारी करने से ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि उनका अनुपालन कितने पारदर्शी व संवेदनशील दृष्टि से किया जाता है। साथ ही विगत के अनुभवों से भी सबक लेकर आगे बढ़ने की जरूरत है।

यह तथ्य किसी से छिपा नहीं कि वर्ष 2012 के निर्भया कांड के बाद देश में कोलकाता कांड में भी उसी तरह की तल्ख प्रतिक्रिया सामने आई है। जिसके बाद आवश्यकता महसूस की गई कि ऐसे क्रूर अपराधियों को सख्त से सख्त सजा देने वाले कानून लाये जाएं। कालांतर देश में यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधि ानियम अस्तित्व में आया। दरअसल, महिलाओं के लिये सुरक्षित कार्यस्थल सुनिश्चित करने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ ही विशाखा दिशा–निर्देशों के विस्तार के रूप में इसे अधिनियमित किया गया। यहां उल्लेखनीय है कि पिछले साल, देश की शीर्ष अदालत ने इस अधिनियम के क्रियान्वयन के संबंध में गंभीर खामियों की ओर इशारा किया था। साथ ही इससे जुड़ी अनिश्चितताओं की ओर भी संकेत दिया था। इसके उदाहरण के रूप में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिये केंद्र सरकार द्वारा स्थापित निर्भया फंड अक्सर नकारात्मक कारणों से सुर्खियों में रहा है। जिसमें आवंटित धन का पर्याप्त रूप में उपयोग न करना या फिर इस आवंटित धन का दुरुपयोग होना शामिल है। करीब एक दशक में देश के विभिन्न राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों के लिये महिला सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिये आवंटित धनराशि का लगभग छिहत्तर फीसदी धन ही खर्च हो पाया है। निश्चित रूप से महिला सुरक्षा की ऐसी चुनौतियों के बीच कम धन का खर्च होना एक विडंबना ही कही जाएगी। वहीं इस दौरान देश में दर्ज किये गए बलात्कार के मामलों की संख्या में केवल नौ फीसदी की ही गिरावट दर्ज की गई है। निश्चित रूप से महिलाओं की सुरक्षा को लेकर शुरू की जाने वाली किसी भी नई पहल पर इन तमाम गंभीर तथ्यों को ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। इसमें दो राय नहीं कि महिलाओं की सुरक्षा और कार्यबल में उनकी बड़ी भागीदारी तब तक अधूरी कही जाएगी, जब तक हम न केवल अपराधियों के खिलाफ बल्कि उन अधिकारियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई नहीं करते, जो अपने कर्तव्य पालन में लापरवाही के लिये दोषी पाये जाते हैं।

बच्चों में बढ़ रही हिंसक प्रवृत्ति

भारतीय बच्चों में बढ़ रही हिंसक प्रवृत्ति चिन्ताजनक है। पिछले कुछ समय से स्कूली बच्चों में बढ़ती हिंसा की प्रवृत्ति निश्चित रूप से डरावनी एवं खौफनाक है। चिंता का बड़ा कारण इसलिए भी है क्योंकि जिस उम्र में बच्चों के मानसिक और सामाजिक विकास की नींव रखी जाती है, उसी उम्र में कई बच्चों में आक्रामकता घर करने लगी है और उनका व्यवहार हिंसक होता जा रहा है। जिस उम्र में बच्चों को पढ़ाई–लिखाई और खेलकूद में व्यस्त रहना चाहिए, उसमें उनमें बढ़ती आक्रामकता, हिंसा एवं क्रूरता एक अस्वाभाविक और परेशान करने वाली बात है। कई घटनाओं में स्कूल में पढ़ने वाले किसी बच्चे ने अपने सहपाठी पर चाकू या किसी घातक हथियार से हमला कर दिया और उसकी जान ले ली। अमेरिका की तर्ज पर भारत के बच्चों में हिंसक मानसिकता का पनपना हमारी शिक्षा, पारिवारिक एवं सामाजिक संरचना पर कई सवाल खड़े करती है। यह दुष्प्रवृत्ति बच्चों के शैक्षणिक प्रदर्शन पर तो नकारात्मक प्रभाव डाल ही रही है, इसे भविष्य में समाज की शांति के लिए बड़ा खतरा भी मानना चाहिए। राजस्थान के उदयपुर के स्कूल में दो छात्रों के आपसी विवाद में चाकू मारने से एक छात्र की मौत भी बच्चों में पनप रहे इसी हिंसक बर्ताव का घिनौना एवं घातक रूप है।

बड़ा सवाल है कि जिन वजहों से बच्चों के भीतर आक्रामकता एवं हिंसा पैदा हो रही है, उससे निपटने के लिए क्या किया जा रहा है! पाठ्यक्रमों का स्वरूप, पढ़ाई–लिखाई के तौर–तरीके, बच्चों के साथ घर से लेकर स्कूलों में हो रहा व्यवहार, उनकी रोजमर्रा की गतिविधियों का दायरा, संगति, सोशल मीडिया या टीवी से लेकर उसकी सोच–समझ को प्रभावित करने वाले अन्य कारकों से तैयार होने वाली उनकी मनःस्थितियों के बारे में सरकार, समाजकर्मी एवं अभिभावक क्या समाधान खोज रहे हैं। बच्चों के व्यवहार और उनके भीतर घर करती प्रवृत्तियों पर मनोवैज्ञानिक पहलू से विचार किए बिना समस्या को कैसे दूर किया जा सकेगा? बच्चों के बस्ते की औचक जांच की व्यवस्था की अपनी अहमियत हो सकती है। मगर जरूरत इस बात की है कि बच्चों के भीतर बढ़ती हिंसा और आक्रामकता के कारणों को दूर करने को लेकर गंभीर काम किया जाए। उदयपुर की घटना के पूरे मामले की पुलिस अपने तरीके से जांच करेगी, लेकिन किशोर अवस्था में ऐसी घटना को अंजाम देने के पीछे बच्चे की मानसिकता का पता लगाना भी ज्यादा जरूरी है। तहकीकात स्कूल की व्यवस्थाओं की भी होनी चाहिए कि आखिर बच्चा स्कूल में हथियार लेकर कैसे आ गया? इसमें दो राय नहीं कि किशोरवय में राह भटकने का खतरा ज्यादा रहता है। उम्र के इस पड़ाव पर उनको सही राह दिखाने की जिम्मेदारी परिजन और शिक्षक की ही होती है। आज दोनों ही कहीं न कहीं अपनी जिम्मेदारी से दूर

होते नजर आ रहे हैं। स्कूल में केवल किताबी ज्ञान पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। वहीं अर्थप्रध ान दुनिया में माता–पिता के पास बच्चों के साथ बिताने के लिए समय ही नहीं बच पा रहा।

'मन जो चाहे वही करो' की मानसिकता वहां पनपती है जहां इंसानी रिश्तों के मूल्य समाप्त हो चुके होते हैं, जहां व्यक्तिवादी व्यवस्था में बच्चे बड़े होते–होते स्वछन्द हो जाते हैं। 'मूड ठीक नहीं' की स्थिति में घटना सिर्फ घटना होती है, वह न सुख देती है और न दुःख। ऐसी स्थिति में बच्चे अपनी अनंत शक्तियों को बौना बना देता है। यह दकियानूसी ढंग है भीतर की अस्तव्यस्तता को प्रकट करने का। पारिवारिक एवं सामाजिक उदासीनता एवं संवादहीनता से ऐसे बच्चों के पास सही जीने का शिष्ट एवं अहिंसक सलीका नहीं होता। वक्त की पहचान नहीं होती। ऐसे बच्चों में मान–मर्यादा, शिष्टाचार, संबंधों की आत्मीयता, शांतिपूर्ण सहजीवन आदि का कोई खास ख्याल नहीं रहता। भौतिक सुख–सुविधाएं ही जीवन का अंतिम लक्ष्य बन जाता है। भारतीय बच्चों में इस तरह का एकाकीपन उनमें गहरी हताशा, तीव्र आक्रोश और विषैले प्रतिशोध ा का भाव भर रहा है। वे मानसिक तौर पर बीमार बन रहे हैं और अपने पास उपलब्ध खतरनाक एवं घातक हथियारों का इस्तेमाल कर हत्याकांड कर बैठते हैं। शिक्षकों और परिजनों से संवादहीनता के चलते बच्चों ने मोबाइल फोन और सोशल मीडिया को संवाद का जरिया बना लिया है। कई बार टी.वी. पर हिंसक कार्यक्रम देखने आदि से बच्चों में हिंसक व्यवहार बढ़ जाता है। घर में लगातार बंदूकें, चाकू आदि देखते रहने से भी बच्चों का व्यवहार हिंसक हो जाता है। वैसे भी अगर बच्चों को किसी भी बात के लिए मना नहीं करेंगें, टोकेंगें नहीं तो उन्हें अच्छे–बुरे की पहचान कैसे होगी। एक ऑनलाइन सर्वे में माता–पिता ने कहा था कि बच्चों को गलत काम की सजा भी मिलनी चाहिए, वरना उनके मन में किसी भी बात के लिए डर नहीं रहेगा और हो सकता है वे ऐसे अपराधों को भी अंजाम देने लगें, जिनके परिणामों के बारे में उन्हें पता नहीं।

स्कूली बच्चों में पिछले कुछ समय से हिंसक प्रवृत्ति तेजी से बढ़ रही है, जो समाज के लिए खतरे की घंटी से कम नहीं है। मनोविज्ञानी यह मानते हैं कि मोबाइल पर पबजी जैसे खतरनाक गेम और वेब सीरीज बच्चों को हिंसक बना रही है। लेकिन, इसके पीछे न सिर्फ स्कूल का वातावरण, बल्कि लाड–प्यार में अंधे अभिभावकों का रवैया भी कम जिम्मेदार नहीं है। बच्चों में हिंसक व्यवहार के संकेत, जैसे गलत भाषा का प्रयोग करना, समझाने पर भी गुस्सा करना, कोई भी बात समझाने पर चीजें फैंकने लगना, मां–बाप को ही मारने दौडना, लोगों के बारे में गलत बोलना, गलत आदतों में पडना, भाई–बहन के लिए स्नेह न रखना, लड़ाकू प्रवृत्ति का होना, हमेशा उदास रहना, संवेदनहीन और चिड़चिड़े रहना, बार–बार जोश में आना आपको नजर आ सकते हैं। एकल परिवारों में माता–पिता इतने व्यस्त होते हैं कि उनके पास बच्चों से बात करने का ज्यादा समय नहीं होता। वे अक्सर इस बात पर भी नजर नहीं रख पाते कि बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या खेल रहे हैं, उनके दोस्त कौन–कौन से हैं। दोस्त उन्हें चिढ़ाते भी हैं कि अरे! तुम्हारे माता–पिता कैसे हैं, जो तुम्हें ऑनलाइन खेल भी नहीं खेलने देते। इससे बच्चों में हीनता और अपने घर वालों के प्रति नफरत का भाव पैदा होता है, जो अपराध ा के रूप में बाहर निकलता है। फिजिकल, ओरल या सैक्सुअल रूप में गलत व्यवहार, घरेलू वातावरण न मिलना, माता–पिता द्वारा बच्चों की अनदेखी, दर्दनाक घटना होने या फिर स्ट्रैस होना, बच्चों को धमकाना, फैमिली प्रॉब्लम, नशीली चीजों का सेवन, शराब और अन्य गलत चीजों के सेवन से बच्चों में आक्रामकता बढ़ सकती है और वे हिंसक हो सकते हैं।ऑस्ट्रिया के क्लागेनफर्ट विश्वविद्यालय की ओर से किशोरों पर किए गए अध्ययन में पता चला है कि दुनिया भर में 35.8 प्रतिशत से ज्यादा किशोर मानसिक तनाव, अनिद्रा, अकारण भय, पारिवारिक अथवा सामाजिक हिंसा, चिड़चिड़ापन अथवा अन्य कारणों से जूझ रहे हैं। एकाकीपन बढ़ने से वे ज्यादा आक्रामक और विध्वंसक सोच की तरफ बढ़ने लगे हैं।

मप्र प्रदेश की मोहन सरकार के दो निर्णयों की यूनिसेफ़ ने भी की सराहना

प्रवीण गुगनानी

पिछले दिनों में मप्र की मोहन यादव सरकार ने दो निर्णय लिए हैं और दोनों ही से वे अपार लोकप्रियता प्राप्त करने जा रहे हैं। प्रदेश की किशोरी छात्राओं हेतु लिए गए एक निर्णय की तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा व प्रसंशा हो रही है। एक निर्णय की अंतर्राष्ट्रीय एक योजना जहां प्रदेश के किसानों हेतु शुभसमाचार है वहीं दूसरी योजना प्रदेश की स्कूली बालिकाओं के लिए प्रसन्न कर देने वाली है। बालिकाओं को निःशुल्क सैनिटरी पेड देने वाली इस योजना की प्रशंसा संयुक्त राष्ट्र संघ, के संगठन यूनिसेफ़ ने भी मुक्त कंठ से की है। देश के कुछ प्रदेशों में छात्राओं को निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन दिये जाते रहे हैं किंतु इस संदर्भ में बालिकाओं को नगद राशि देने वाला प्रथम राज्य मप्र बन गया है। इस प्रकार नगद राशि से बालिकाऐं अपनी पसंद व आवश्यकतानुसार सामग्री स्वयं क्रय सकेंगी। मप्र के मुख्यमंत्री मोहन यादव की सैनिटेशन एवं हाईजीन योजना को यूनिसेफ़ ने एक उत्कृष्ट योजना बताया है। यूनिसेफ़ ने एक्स (ट्विटर) पर अपने एकाउंट में लिखा कि यह एक अनूठा नवाचार है और प्रसंशा करते हुए इस योजना को शुभकामनाएँ दे है। डॉ. मोहन यादव ने भी अपने X अकाउंट पर UNICEF को इस योजना की प्रसंशा करने हेतु धन्यवाद देते हुए कहा है– "मध्य प्रदेश के किशोरों और बच्चों के लिए काम करने की हमारी प्रतिबद्धता को विश्व स्तर पर मान्यता देने के लिए /UNICEFIndia को हार्दिक धन्यवाद। यूनिसेफ पूर्व से ही (UNICEF) की भारतीय इकाई भारत सरकार के साथ मिलकर स्कूल हाईजीन और मासिक धर्म संबंधी स्वास्थ्य जागरुकता (Menstrual Health Awarenè) की दिशा में अभियान चलाये हुए है। विगत सप्ताह मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने छात्राओं के सम्मान व उनसे संवाद के एक कार्यक्रम में समग्र शिक्षा अभियान के अंर्तगत प्रदेश की उन्नीस लाख छात्राओं के खाते में सत्तावन करोड़ अट्ठारह लाख रू. की राशि सैनिटरी नैपकिन हेतु ट्रांसफ़र कर दी थी। यह राशि कक्षा सातवीं से बारहवीं तक की छात्राओं को दी जाएगी जिससे वे स्वयं नैपकिन क्रय कर सकेंगी। इस योजना से उन्हें एक वर्ष हेतु तीन सौ रु. मिलेंगे। इस योजना के अंर्तगत समग्र शिक्षा अभियान में विद्यालयों व महाविद्यालयों की छात्राओं को मासिक धर्म के समय स्वच्छता की महत्व और महत्व को भी बताया जाना है। प्रदेश में पूर्व से ही महिला एवं बाल विकास की एक उदिता योजना भी कार्यरत है जिसमें अट्ठारह से उन पचास आयु वर्ग की महिलाओं आंगनवाड़ी के कार्यकर्ताओं द्वारा लाभ दिया जाता है। चर्चा में आई कृषक व श्रीअन्न आधारित दूसरी योजना भी राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उल्लेखनीय होने जा रही है। मप्र के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश के किसानों हेतु रानी दुर्गावती श्रीअन्न प्रोत्साहन योजना लागू की है। कृषक जगत हेतु महत्वपूर्ण इस योजना में श्रीअन्न जैसे कोदो, कुटकी, रागी, ज्वार, बाजरा, कंगनी, सांवा आदि को उपजाने वाले कृषक बंधुओं को प्रति किलो 10 रुपये दिए जाएंगे। कृषकों को दस रू. प्रति किलोग्राम दस रुपये देने की योजना जहां देश के लिए बड़ी मात्रा में श्रीअन्न उपजाने हेतु प्रेरणा व आर्थिक संबल देगी वहीं कृषकों, विशेषतः जनजातीय कृषकों हेतु वरदान सिद्ध हो सकती है। हमारे प्रदेश के जनजातीय पूर्व से ही इन मोटे अनाजों को उपजाते व खाते रहें हैं किंतु अब इस योजना से वे श्रीअन्न का उत्पादन बढ़ायेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भारत की पहल पर वर्ष 2023 को श्रीअन्न वर्ष घोषित किया था। प्रधानमंत्री जी, नरेंद्र मोदी भी श्रीअन्न को अपने भाषणों व कथनों में स्थान देते रहते हैं जिससे देश में मोटा अनाज खाने का एक सुदृढ़ वातावरण बन गया है। इस स्थिति में इन अनाजों हेतु बाज़ार बढ़ना ही है। अब इस योजना से मप्र के कृषक विशेषतः जनजातीय कृषक विषे तौर पर लाभान्वित होंगे। कृषकों को उनकी प्रोत्साहन राशि सीधे उनके खाते में अंतरित की जाएगी। ये अनाज प्रमुख रूप से मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, शहडोल, अनूपपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, सीधी और सिंगरौली जैसे जनजातीय बहुल जिलों में उगाए जाते हैं। प्रदेश में मोटे अनाजों के उत्पादन, प्रसंस्करण

और विपणन पर केंद्रित एक सम्मेलन का आयोजन भी पूर्व में हो चुका है। प्रदेश के डिंडोरी ज़िले में श्रीअन्न अनुसंधान संस्थान केंद्र के निर्माण की भी घोषणा हो चुकी है। यद्दपि वर्तमान में मप्र, देश के मोटे अनाज के उत्पादन में केवल 3.5 प्रतिशत का योगदान देता है वहीं राजस्थान में देश का 33 प्रतिशत व कर्नाटक में 23 प्रतिशत रकबे में इसकी कृषि की जाती है। मोटे अनाज स्वास्थ्य की दृष्टि से अत्यधिक उपयोगी व लाभप्रद होते हैं। इनमें खनिज, मिनरल्स व प्रोटीन्स की मात्रा अत्यधिक होती है। इन सभी गुणों के कारण श्रीअन्न को कई बीमारियों के निदान हेतु भी उपयोग किया जाने लगा है। वर्तमान समय में मप्र में छः लाख बीस हजार हेक्टेयर भूमि पर मोटा अनाज उत्पादित किया जा रहा है जबकि वर्ष 2021–22 में यह पांच लाख पचपन हजार हेक्टेयर पर ही श्रीअन्न उपजाया जाता था। मप्र देश में मोटे अनाजों के उत्पादन में पाँचवें न. पर है। वर्ष 2023–24 में प्रदेश में 12.68 लाख टन मोटे अनाजों का उत्पादन हुआ, जो 2019–20 में 8.96 लाख टन था। प्रदेश में सबसे अधिक लगभग 60 प्रतिशत बाजरा उगाया जा रहा है।

प्रदेश के कृषकों को दस रुपये प्रति किलोग्राम की प्रोत्साहन राशि व शालेय किशोरियों को सैनिटरी नैपकिन देने की योजना से निश्चित ही मप्र की मोहन सरकार देश भर में अग्रणीं होने जा रही है।

– मप्र के महाकोशल के मंडला, डिंडोरी, बालाघाट आदि जिलों में श्रीअन्न का ज्यादा उत्पादन होता है।

– उत्पादन क्षेत्र नहीं बढ़ने की बड़ी वजह यह भी है कि प्रदेश में इसकी बड़ी खाद्य प्रसंस्करण इकाई नहीं हैं।

– देशभर में कुल खाद्यान्न उत्पादन के 10 प्रतिशत हिस्से में मोटा अनाज उगाया जा रहा है।

– राजस्थान में सर्वाधिक 33 और कर्नाटक में कुल खाद्यान्न 23 प्रतिशत क्षेत्र में श्रीअन्न का उत्पादन किया मप्र के महाकोशल के मंडला, डिंडोरी, बालाघाट आदि जिलों में श्रीअन्न का ज्यादा उत्पादन होता है।

– उत्पादन क्षेत्र नहीं बढ़ने की बड़ी वजह यह भी है कि प्रदेश में इसकी बड़ी खाद्य प्रसंस्करण इकाई नहीं हैं।

– देशभर में कुल खाद्यान्न उत्पादन के 10 प्रतिशत हिस्से में मोटा अनाज उगाया जा रहा है।

– राजस्थान में सर्वाधिक 33 और कर्नाटक में कुल खाद्यान्न 23 प्रतिशत क्षेत्र में श्रीअन्न का उत्पादन किया जा रहा है। ऐसी ही प्रोत्साहन योजनाओं व कृषकोंको मिल रही नियोजित मार्केटिंग की योजनाओं व अच्छे मूल्यों के प्राप्त होने के चलते ही मप्र में जहां वर्ष 2019–20 में आठ लाख छ्यानवे हज़ार मेट्रिक टन का उत्पादन होता था वहीं 2023–24 में मोटे अनाज का यह उत्पादन बारह लाख अड़सठ हज़ार टन का हो गया है।

जुगलबंदी से मधुर साज और आवाज़

केवल तिवारी

इसे सुखद संयोग ही कहेंगे किएक तरफ चंडीगढ़ में 'वर्षा ऋतु संगीत संध्या' चल रही थी, दूसरी तरफ बाहर रिमझिम फुहार। गीतों के बोल भी ऐसे ही थे, मसलन 'गरजे घटा घन कारे–कारे', 'घन घनन घनन घन घोर', 'गरजत आये री बदरवा', 'बूंदनीया बरसे', 'झुक आयी बदरिया सावन की' वगैरह–वगैरह। पिछले दिनों इस कार्यक्रम में प्रस्तुति देने पहुंचे थे शास्त्री संगीत में साज और आवाज के तीन दिग्गज। 'दैनिक ट्रिब्यून' के साथ बातचीत में इन लोगों ने साज, संगीत और आज के वातावरण पर विस्तार से बातचीत की। पेश है तीनों कलाकारों से हुई बातचीत के चुनींदा अंश रू–

परंपरा को बढ़ाया : विदुषी मीता पंडित

विदुषी मीता पंडित, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की एक अग्रणी और लोकप्रिय गायिका हैं। उन्होंने भारत और 25 से अधिक देशों में श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किया है। विदुषी मीता ऑल इंडिया रेडियो की एक शीर्ष श्रेणी की कलाकार हैं। सूफी, ठुमरी, भक्ति और सुगम शैलियों में उनकी प्रस्तुति समान रूप से भावपूर्ण है। ग्वालियर घराने से ताल्लुक रखने वाली विदुषी मीता पंडित का मानना है संगीत के प्रति अनुराग किसी के भी तन–मन को झंकृत करता है। उन्होंने कहा कि यह शास्त्रीय संगीत की सुमधुरता ही है कि देश के कोने–कोने के अलावा विदेशों में भी इसको लेकर कार्यक्रम होते हैं और लोग बहुत चाव से इसे सुनते हैं। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के पुरोधा रहे पद्म भूषण पं. कृष्णराव शंकर पंडित की पोती एवं पं. लक्ष्मण कृष्णराव पंडित की बेटी मीता पंडित का भी रुझान बचपन से ही संगीत की ओर रहा। उन्होंने अपने पुश्तैनी परंपरा को तो आगे बढ़ाया ही, आज की पीढ़ी को भी संगीत के सुरों को समझाया। मीता आज के तड़क–भड़क के गीत संगीत और शास्त्रीय संगीत के बीच किसी तरह की तुलना करने से ही इनकार कर देती हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि दोनों संगीतों और दोनों के श्रोताओं में तुलना का सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने यह दावा जरूर किया कि अगर शास्त्री संगीत की समझ रखी जाये और इसे गौर से सुना जाये तो लोग इसके मुरीद होते हैं। उन्होंने कहा कि संगीत के शौक का उम्र से कोई लेना–देना नहीं।

प्रयोग की संभावना : डॉ. अविनाश कुमार

दिल्ली विश्वविद्यालय के डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज में संगीत के शिक्षक डॉ. अविनाश कुमार मानते हैं कि शास्त्रीय संगीत में प्रयोग की पूरी संभावना है। वह कहते हैं न केवल संभावना है, बल्कि ऐसा किया जाना

जरूरी है। क्योंकि आज के समय में एक ही राग पर आधारित किसी गीत को घंटों सुनने का लोगों के पास वक्त नहीं। कुमार मानते हैं कि आज युवा शास्त्रीय संगीत की तरफ पूरी तरह से आकर्षित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि शास्त्रीय संगीत के माहौल में पले–बढ़े बच्चों का चित्त शांत रहता है। युवा हिंदुस्तानी शास्त्री गायक डॉ. अविनाश कुमार ने साधना चटर्जी और पूर्णचंद्र चटर्जी से शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ली। बाद में उन्होंने रामपुर सहसवान घराने के उस्ताद आफताब अहमद खान से उन्नत प्रशिक्षण प्राप्त किया। उन्होंने आगरा और किराना घराने के पंडित तुषार दत्त और किराना घराने के पंडित सोमनाथ मर्दुर से संगीत का भी प्रशिक्षण लिया।

मां से सीखा तबला : पं. राम कुमार मिश्र

शीर्ष तबला वादक पंडित राम कुमार मिश्र का मानना है कि भारतीय साज और आवाज को आगे बढ़ाने में युवाओं को आगे आना चाहिए। जाने–माने तबला वादक पंडित अनोखे लाल मिश्र के पौत्र एवं पद्म विभूषण पंडित छन्नू लाल मिश्र के पुत्र राम कुमार को तबले की तालीम उनकी मां मनोरमा मिश्र से मिली। उन्होंने कहा कि अब इस परंपरा के उनके पुत्र आगे ले जा रहे हैं। बनारस घराने के तबला वादक कुमार कहते हैं कि कार्यक्रमों के दौरान प्रत्येक दर्शक से वह कनेक्ट होते हैं और जिस तरह गायन शैली में परिवर्तन हो रहा है, प्रयोग हो रहे हैं, तबले की ताल में भी प्रयोग की हमेशा गुंजाइश बनी रहती है।

जिन्दगी से खेलते मिलावटी दूध के कारोबारी

इसमें कोई दो राय नहीं है कि मिलावट अब एक बेरोकटोक चलने वाली समस्या बन गई है। हर तरह की मिलावटों के खिलाफ कानून बनाए गए हैं, लेकिन उनका असर न के बराबर है। खाद्यान्न के अलावा पेय पदार्थों, तेलों, शहद और दूध में मिलावट बहुत बड़े पैमाने पर होती है। सरकारी और गैर–सरकारी दोनों तरह के दूध मिलावटी हो गए हैं। विडंबना देखिये कि सदियों से कहा जाता रहा है कि दूध बलवर्धक व स्वास्थ्यवर्धक पेय पदार्थ है। आज के दौर में खाने–पीने की चीजों में तमाम रासायनिक पदार्थों की मिलावट के बाद एक दूध से उम्मीद होती है कि बच्चे दूध पीकर तंदुरुस्त बनें। लेकिन जब वे रासायनिक पदार्थों से बना दूध पीएंगे तो उनका क्या स्वास्थ्य सुधरेगा? कल्पना कीजिए कि किसी मरीज को डॉक्टर स्वस्थ होने के लिये दूध पीने को कहे और वह नकली दूध पीने से और बीमार पड़ जाए।

पंजाब, जहां प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता देश में सर्वाधिक है, वह मिलावटी दूध के दाग को धोने के लिये संघर्षरत है। पिछले तीन वर्षों में राज्य में एकत्र किए गए दूध व दूध से बने उत्पादों के लगभग 18 प्रतिशत नमूने फेल हुए हैं। वहीं दूध–दही के खाने के लिये प्रसिद्ध हरियाणा में भी 28 फीसदी नमूने मानक कसौटी पर खरे नहीं उतरे । जैसे–जैसे त्योहारी सीजन नजदीक आ रहा है नमूने भरने, तलाशी लेने और मिलावट करने वालों की धरपकड़ की रस्मी कार्रवाई तेज हो जाएगी। लेकिन अब तक सुना नहीं गया कि किसी दोषी को कोई बड़ी सजा मिली हो।

सर्वोच्च न्यायालय ने दिसंबर 2011, दिसंबर 2014 और अगस्त 2016 में केंद्र और राज्य सरकारों को मिलावटखोरी के खिलाफ सख्त कानून बनाने की सलाह दी थी। गौरतलब है कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली सहित देश के विभिन्न हिस्सों में दूध में मिलावट को लेकर 2011, 2016 और 2018 में सर्वेक्षण कराए गए थे। जगजाहिर है कि नेशनल सर्वे रिपोर्ट से यह जाहिर हो चुका है कि दूध में खतरनाक एल्फोटोक्सिन और एंटीबायोटिक्स मिलाया जाता है, जिससे हमारा लीवर हमेशा के लिए खराब हो सकता है या हम कैंसर जैसी बीमारी की चपेट में आ सकते हैं। आंख, आंत, गुर्दे हमेशा के लिए हमारा साथ छोड़ सकते हैं। मिलावटी दूध पीने से बच्चों की ही नहीं, बल्कि बड़ों की हड्डियां भी कमजोर हो जाती हैं।

यह मानवीय मूल्यों के पराभव की पराकाष्ठा है कि दूध की जगह रासायनिक पदार्थों से बना जहरीला पदार्थ धड़ल्ले से बिक रहा है। हकीकत में दूध दुनिया में सबसे ज्यादा मिलावटी खाद्य पदार्थ है, लेकिन भारत में यह संकट बड़ा है। वैसे भारत पिछले दो दशक से दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है। लेकिन लगातार पशुधन संख्या में गिरावट के बावजूद दूध से जुड़े आंकड़े संदेह भी पैदा करते हैं।

दूध में पानी मिलाने की कथाएं तो सदियों पुरानी हैं। लेकिन हाल के दशकों में उन खबरों ने डराया है, जिनमें कहा गया कि आपराधिक मानसिकता के मुनाफाखोर दूध में डिटर्जेंट, यूरिया, ग्लूकोज और फॉर्मेलिन आदि मिला रहे हैं। दूध में मेलामाइन मिले होने की पहचान यह है कि धूप में रखने पर दूध का पैकेट फूल कर गुब्बारा हो जाता है। वहीं दूसरी ओर रेलवे स्टेशनों व बस स्टैंडों पर भी लगातार नकली दूध की चाय बिकने की शिकायतें आती रही हैं।

कुछ वर्ष पहले उ.प्र. के एक रेलवे स्टेशन में सफेद रंग से बने दूध की चाय बिकने की शिकायत सामने आई थी। लेकिन इसके बावजूद इस मिलावट पर अंकुश लगाने के लिये हितधारकों की तरफ से कोई गंभीर प्रयास होते नजर नहीं आते। यह दुखद ही है कि हर घर में प्रयुक्त होने वाले दूध की गुणवत्ता में भारी गिरावट के बाद भी शासन–प्रशासन की दृष्टि में यह गंभीर मुद्दा नहीं है। न ही राजनीतिक दल ही इस गंभीर मुद्दे को संबोधित करते हैं। जिसकी वजह से मिलावट करने वालों के हौसले बुलंद हैं।

गौरतलब है कि बिना किसी सरकारी मदद के देश में दूध का सत्तर फीसद कारोबार असंगठित ढांचा संभाल रहा है। देश में दूध उत्पादन में छियानबे हजार सहकारी संस्थाएं जुड़ी हुई हैं। चौदह राज्यों में अपनी दुग्ध सहकारी संस्थाएं हैं। ये संस्थाएं लाखों लीटर दूध का संग्रह करती हैं। आम आदमी इन सहकारी दूध उत्पादक संघों द्वारा संग्रहित या उत्पादित दूध पर यकीन और आंख मूंद कर इस्तेमाल करता है। अगर इन ब्रांडों में भी मिलावट होने लगे तो, इन पर से विश्वास उठना लाजमी है।

हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडीशा, उत्तराखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ सहित देश के तमाम राज्यों से दूध में मिलावट की खबरें आती रही हैं। साल 2023 में उत्तराखंड के दूध उत्पादक सहकारी संघ द्वारा उत्पादित दूध श्आंचलश् में मेलामाइन नामक जहरीले रसायन मिलाए जाने की खबर आई, तो लोगों ने सहकारी उत्पादक संघों की ईमानदारी पर सवाल उठाए।इसी तरह पिछले दशक में पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडीशा जैसे राज्यों में कृत्रिम दूध बनाने और दूध में मिलावट से कई लोगों में खतरनाक बीमारियां होने का मुद्दा सुर्खियों में रहा।

मिलावट की वजह से श्वेत–क्रांति का कारवां रुकता नजर आ रहा है। गौरतलब है कि दूध में हो रही बड़े पैमाने पर मिलावट और बढ़ते पशु–वध की वजह से श्वेत–क्रांति के कदम डगमगा रहे हैं। यह मिलावट दूध उत्पादक सहकारी संघों और निजी उत्पादकों के अलावा बिक्री करने वाले अनपढ़ दूधिए भी करते हैं। इसलिए दूध में मिलावट के खिलाफ सरकारी और गैर सरकारी अभियान साल के बारहों महीने चलाने की जरूरत महसूस होने लगी है। दूध में मिलावट का मतलब दूध से बनने वाले सभी उत्पादों में मिलावट होना।बहरहाल, आज यदि समाज में सेहत के लिये घातक रासायनिक पदार्थों से बना नकली दूध धड़ल्ले से बिक रहा है तो स्वाभाविक प्रश्न है कि जिन खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के पास खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने का जिम्मा है, क्या वे ईमानदारी से अपने दायित्वों को निभा रहे हैं? दरअसल, इन मलाईदार पदों पर नियुक्ति में जिस तरह धनबल व राजनीतिक बल चलता है, वह पद कालांतर सोने का अंडा देने वाली मुर्गी में बदल जाता है। तभी दिवाली आदि त्योहारों में मिठाई के लिये बाजार में दूध, मावे और पनीर की बाढ़ आ जाती है, लेकिन ऐसी स्थिति वर्ष के शेष महीनों में नहीं होती। सवाल स्वाभाविक है कि दिवाली व अन्य त्योहारों के समय दूध व उसके उत्पादों से जो बाजार भर जाता है, साल के शेष महीनों में वह दूध आदि क्यों नजर नहीं आता? इस खेल की तह तक जाने की जरूरत है। वहीं क्या उपभोक्ताओं को मिलावटी दूध से स्वास्थ्य को पैदा होने वाले खतरों के प्रति जागरूक किया जाता है?

इससे दूध उत्पादक पशुपालकों और दूधियों की बदनामी हुई। समाज में असहजता पैदा हुई। जिससे कई तरह की समस्याएं पैदा हुई, लेकिन मिलावट का सिलसिला रुका नहीं। श्वेत–क्रांति के सफल न होने के पीछे दूध में बड़े पैमाने पर हो रही मिलावट और दूध देने वाले जानवरों की बढ़ती गोकशी प्रमुख वजह मानी जाती है। दरअसल, इन मामलों में कड़ी सजा न मिलने से मिलावट करने वालों के हौसले बुलंद रहते हैं। उन्हें पता है कि आखिरकार येन–केन–प्रकारेण वे बच ही जाएंगे।अहम बात यह है कि आम उपभोक्ता के लिये दूध में मिलावट की पहचान करने वाली किट बाजार में सहजता से उपलब्ध हों। इस किट को किफायती, उपयोगकर्ता के अनुकूल तथा सटीक जानकारी देने वाला बनाया जाए। खाद्य सुरक्षा एजेंसियों को उत्पादों की जांच, नमूने लेने तथा दोषी पाये जाने पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। नियम के मुताबिक मिलावट को रोकने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं मानक कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, मगर ऐसी कोई कार्रवाई नहीं होती, जो मिलावटखोरों के लिए सबक बने।

बलात्कार मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट जरूरी

कोलकाता में एक युवा डाक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के बर्बर मामले ने पूरे देश की अंतरात्मा को झकझोर दिया है। मामले और उसके बाद की घटनाओं को ठीक से न संभाल पाने के कारण उच्च न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ा और सी.बी.आई. जांच का आदेश देना पड़ा। सर्वोच्च न्यायालय ने भी हस्तक्षेप किया और चिकित्सा पेशेवरों की सुरक्षा के लिए उपाय सुझाने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन करने के अलावा राज्य सरकार के खिलाफ सख्त कदम उठाए। आज के समाचार पत्रों में उपरोक्त शीर्षक के साथ–साथ एक और परेशान करने वाली खबर थी। अजमेर में सैंकड़ों लड़कियों से सामूहिक बलात्कार और यौन शोषण के मामले में 6 आरोपियों को दोषी करार दिया गया और सजा सुनाई गई। दुखद विडंबना यह थी कि अपराध के 32 साल बाद दोषसिद्धि हुई।

हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली में अभियोजन की यह धीमी प्रक्रिया आंशिक रूप से ऐसे बर्बर अपराधों की आवृत्ति और अपराधियों में कानून के डर की कमी को स्पष्ट करती है। जबकि सैंकड़ों लड़कियों का यौन शोषण किया गया था, पुलिस ने 18 पुरुषों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था।

केवल 30 पीड़ित ही शिकायत दर्ज कराने के लिए आगे आए और उनमें से केवल 2 ने ही अंत तक लड़ाई लड़ी। सैंकड़ों या शायद हजारों स्थगन और सुनवाई के बाद अदालत ने आखिरकार 32 साल की लंबी देरी के बाद 6 आरोपियों को दोषी ठहराया और सजा सुनाई। कोलकाता बलात्कार और हत्या मामले में हस्तक्षेप करते हुए सुप्रीम कोर्ट को खुद के साथ–साथ न्यायिक प्रणाली की ओर भी ध्यान देना चाहिए था कि सिस्टम में क्या गलत है। जाहिर है कि यह कोई अपवाद नहीं है। अक्सर ऐसी खबरें आती हैं कि न्यायिक प्रक्रिया में सालों–साल लग जाते हैं जिससे अपराधियों को रोकने का उद्देश्य विफल हो जाता है।

2012 में दिल्ली में एक छोटी लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार और अत्याचार के कुख्यात निर्भया मामले के मद्देनजर देश ने काफी आघात झेला था। पूरे देश का ध्यान इस पर होने के बावजूद, 2020 में मामले के 6 आरोपियों में से 4 को फांसी पर लटकाए जाने में 8 साल लग गए। बलात्कार और हत्या के मामले अक्सर मीडिया में आते हैं और बलात्कार के कई मामले ऐसे होंगे जो रिपोर्ट नहीं किए जाते होंगे। आज के अखबारों में भी ठाणे के बदलापुर में एक सफाई कर्मचारी द्वारा स्कूल में दो 4 साल की मासूम बच्चियों के साथ बलात्कार की खबर है। ऐसा लगता है कि इस तरह के अपराध करने वालों की बर्बरता की कोई सीमा नहीं है। कई मामलों में आरोपियों के बच्चे पीड़ितों से बड़े होते हैं। निर्भया मामले में आरोपी की तरह कम उम्र के अपराधी भी होते हैं। जाहिर है कि हमारे समाज में और बच्चों के लालन–पालन और उन्हें संस्कार देने के तरीके में कुछ गंभीर गड़बड़ है। दुर्भाग्य से हमारे समाज के बड़े हिस्से में लड़के और लड़की के बीच भेदभाव एक कठोर वास्तविकता है। लड़के को लड़की पर अधिकार दिए जाने की भावना हावी होने और लड़कियों को कमतर समझने के अधिकार में बदल जाती है। माता–पिता अपने बच्चों की मानसिकता को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और कम से कम बच्चों के वयस्क होने तक उन्हें अपने कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। समग्र रूप से समाज, तथा विशेष रूप से राजनीतिक नेता भी, इस बीमार समाज के लिए उत्तरदायी हैं जिसमें हम रह रहे हैं। बिलकिस बानो सामूहिक बलात्कार मामले में दोषियों की रिहाई पर माला पहनाने तथा मिठाई बांटने को कैसे उचित ठहराया जा सकता है, जबकि न तो सरकार, न ही भारतीय जनता पार्टी या आर.एस.एस. (जिससे बलात्कारियों का स्वागत करने वाले लोगों का समूह जुड़ा था) ने घटना की निंदा की।

सुप्रीम कोर्ट और सरकार एक और समिति गठित करके अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते। ऐसी दर्जनों समितियों की रिपोर्ट उपलब्ध हैं और उन पर अमल नहीं किया गया है।

समर्थ समाज और सशक्त राष्ट्र की बुनियादी आवश्यकता है शिक्षा, सीएम योगी ने किया 'रोड टू स्कूल' का शुभारंभ

संवाददाता–गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसी भी समर्थ और सशक्त राष्ट्र की सबसे प्रमुख उपलब्धि शिक्षा होती है। शिक्षा सभ्य व समर्थ समाज और सशक्त राष्ट्र की बुनियादी आवश्यकता है। शिक्षा के बिना मानवीय मूल्यों और जीवन सृष्टि की आवश्यकताओं की पूर्ति की कल्पना नहीं की जा सकती है। सीएम योगी मंगलवार को गोरखपुर के चरगांवा ब्लॉक के लिए निपुण भारत मिशन के तहत प्रदेश में 'रोड टू स्कूल' के पहले प्रोजेक्ट का शुभारंभ कर रहे थे। चरगांवा ब्लॉक क्षेत्र के एक रिजॉर्ट में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। व्यक्ति आत्मनिर्भर होगा तो समाज और राष्ट्र भी आत्मनिर्भर होगा। ऐसे में कोई कारण नहीं कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनने से वंचित रह जाए। उन्होंने शिक्षा के महत्व की चर्चा करते हुए कहा कि प्राचीन समय से अलग अलग कालखंडों में शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के प्रयास किए गए। इसमें गुरुकुल प्रणाली भी प्रेरक रही। तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, काशी, कांचीपुरम की ख्याति अध्ययन और अध्यापन के बेहतरीन केंद्र के रूप में रही। प्राचीनकाल के अलावा बदले हालात में देश को आजादी मिलने के बाद भी शिक्षा के क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए प्रयास हुए लेकिन अभी भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। सीएम योगी ने पिछले सात सालों से सरकार के प्रयासों से प्रदेश के परिषदीय स्कूलों की दशा में आए बदलाव का उल्लेख करते हुए कहा कि 2017 के पहले ड्रापआउट एक बड़ी समस्या थी। बड़ी संख्या में नामांकित बच्चे भी स्कूल नहीं आते थे तो कई कक्षा पांच के बाद छह में और कक्षा आठ के बाद नौ में एडमिशन नहीं लेते थे। सरकार ने स्कूल चलो अभियान में शिक्षकों की भूमिका को महत्व दिया तो आज ये समस्या दूर होती जा रही है।

स्कूल चलो अभियान का परिणाम है कि 2017 के बाद यूपी के परिषदीय विद्यालयों में 50 से 60 लाख नए बच्चे बढ़े हैं। बीच के दो साल कोरोना से प्रभावित होने के बावजूद इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या 1.34 करोड़ से बढ़कर 1.92 करोड़ हो गई है। उन्होंने कहा कि जब हम बच्चों का भविष्य उज्ज्वल बनाएंगे तो भारत का भविष्य उज्ज्वल बनाने में सफल होंगे। स्कूली शिक्षा को मजबूत करने के लिए संसाधन से लेकर प्रोत्साहन तक दिए गए ध्यान का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जनप्रतिनिधियों और मानिंद लोगों को साथ लेकर प्रदेश में बड़ी संख्या में ऑपरेशन कायाकल्प के तहत स्कूलों को सुदृढ़ बनाया गया है। यहां शानदार फर्नीचर व अन्य सुविधाओं के साथ स्मार्ट क्लास बनाए गए हैं।

बच्चों को स्कूल आने के लिए प्रोत्साहित करने को यूनिफॉर्म, कॉपी किताब, बैग, जूता मोजा आदि के लिए सरकार हर बच्चे के अभिभावक को 1200 रुपये की धनराशि देती है। बालिकाओं की शिक्षा के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों को संसाधन सम्पन्न बनाया जा रहा है। श्रमिकों के पाल्यों की मुफ्त शिक्षा के लिए सभी मंडल मुख्यालय पर अटल आवासीय विद्यालय खोले गए हैं। जल्द ही 57 जिलों में डे स्कूल खोले जाएंगे। शिक्षा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए ही पीएम श्री और मुख्यमंत्री कम्पोजिट विद्यालय स्थापित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब मिलकर प्रयास होंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप निपुण भारत मिशन से निपुण उत्तर प्रदेश के निर्माण के लिए हम सफल होंगे।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि रोड टू स्कूल प्रोजेक्ट स्कूल चलो अभियान का ही नया रूप है। इसमें रिसोर्स पर्सन और उनके ऊपर की टीम एक पिरामिड के रूप में बच्चों को स्कूल लाने, उनकी उपस्थित बनाए रखने और उनके शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल और कला कौशल की मॉनिटरिंग करती है। रोड टू स्कूल में बच्चों को उदाहरण देकर सिखाने ओर जोर है। यह एक अभिनव कार्यक्रम है जो बच्चों के शत प्रतिशत नामांकन, कक्षा में उनकी नियमित उपस्थिति और आगे की कक्षाओं में प्रवेश के लिए संवेदनशील प्रयास करता है। शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए जो तमाम प्रयास हो रहे हैं, रोड टू स्कूल उसी का हिस्सा है। बेसिक शिक्षा विभाग के साथ मिलकर 'रोड टू स्कूल' प्रोजेक्ट शुरू करने के मुख्यमंत्री ने अशोक लीलैंड लिमिटेड और उसके कार्यान्वयन भागीदार लर्निंग लिंक फाउंडेशन को धन्यवाद दिया। सीएम योगी ने बताया कि रोड टू स्कूल प्रोजेक्ट के तहत पहले चरण में चरगांवा ब्लॉक के सभी 78 परिषदीय विद्यालयों (प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और कम्पोजिट) को शामिल किया गया है। इससे 17781 विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। दूसरे चरण में भटहट ब्लॉक के सभी 90 परिषदीय विद्यालयों के 16434 छात्रों को फायदा होगा। रोड टू स्कूल प्रोजेक्ट में परिषदीय विद्यालयों में बच्चों का नामांकन बढ़ाने, ड्राप आउट रोकने, बच्चों में पठन–पाठन के प्रति अभिरुचि बढ़ाने, उनके स्वास्थ्य देखभाल और उन्हें खेल एवं कौशल के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने आह्वान करते हुए कहा कि शिक्षक नए भारत के निर्माता हैं। ऐसे में उनकी जिम्मेदारी है कि वे बच्चों को पढ़ाने के लिए खुद को भी ज्ञान के विविध आयामों से अपडेट रखें। उन्होंने कहा कि शिक्षकों को अपने विषय और फील्ड के साथ सामाजिक दायित्वों की भी जानकारी होनी चाहिए ताकि वे बच्चों को योग्य नागरिक बना सकें। खुद को अपडेट रखकर ही वे बच्चों को कुशल बना पाएंगे और आने वाली पीढ़ी उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करेगी।

सीएम ने सुनी फरियाद, भूमाफियाओं को जेल भेजने के दिए निर्देश

संवाददाता–गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा है कि गरीबों को उजाड़ने का दुस्साहस करने वाले माफिया, दबंगों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। गरीबों की जमीन तो बचाई ही जाएगी, साथ ही जिन भी जरूरतमंदों को अभी पक्का मकान नहीं मिल पाया है, उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना के दायरे में लाकर पक्के आवास की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। सीएम योगी ने उक्त निर्देश मंगलवार को गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन के दौरान लोगों की समस्याएं सुनते हुए दिए। मुख्यमंत्री ने इस दौरान करीब 300 लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं। महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन सभागार में कुर्सियों पर बैठाए गए लोगों तक सीएम योगी खुद पहुंचे और समस्या सुनते हुए उनके प्रार्थना पत्र लिए।

उनकी बात इत्मीनान से सुनने के बाद पास में खड़े अधिकारियों को समस्या समाधान हेतु आवश्यक दिशानिर्देश दिए। अलग–अलग मामलों से जुड़े समस्याओं के निस्तारण के लिए उन्होंने संबंधित प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों को प्रार्थना पत्र संदर्भित कर निर्देशित किया कि सभी समस्याओं का निस्तारण समयबद्ध, निष्पक्ष और सन्तुष्टिपरक होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने लोगों को आश्वस्त किया कि प्रभावी कार्रवाई करते हुए सबकी समस्या का समाधान हर हाल में किया जाएगा। जमीन कब्जा किए जाने की कुछ शिकायतों पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट हिदायत दी कि किसी की जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले, कमजोरों को उजाड़ने वाले किसी भी सूरत में बख्शे न जाएं। उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए।

सरकार किसी के भी साथ अन्याय नहीं होने देने और हर व्यक्ति के जीवन में खुशहाली लाने को संकल्पित है। सीएम योगी ने कहा कि राजस्व व पुलिस से संबंधित मामलों में प्रभावी कार्रवाई हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारी जन कल्याण के कार्यों को सदैव प्राथमिकता पर रखें और हर पीड़ित की समस्या का त्वरित निस्तारण करना सुनिश्चित करें। जनता दर्शन में हर बार की तरह इस बार भी कई लोग गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए आर्थिक मदद की गुहार लेकर आए थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें भरोसा दिलाया कि पैसे के अभाव में किसी का इलाज नहीं रुकेगा।

उन्होंने अफसरों को निर्देश दिया कि जो भी जरूरतमंद हैं, प्रशासन उनके उच्च स्तरीय इलाज का इस्टीमेट शीघ्रता से बनवाकर उपलब्ध कराए। इस्टीमेट मिलते ही सरकार तुरंत धन उपलब्ध कराएगी। जन स्वास्थ्य की रक्षा सरकार की प्राथमिकता है।

जीजा की धमकी से तंग दो सगी बहनें नदी में कूदीं, मौत

संवाददाता–गोण्ड। जीजा की धमकी से तंग दो सगी बहनों ने रक्षाबंधन के दिन बिसुही नदी में कूद कर जान दे दी। मृतका सुनीता देवी के पिता सुरेश कुमार की तहरीर पर आरोपी दामाद अशोक कुमार के खिलाफ आत्महत्या के लिए मजबूर करने का मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने आरोपी जीजा को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। मामला कोतवाली मनकापुर के तामापार गांव के मजरा गोफा से जुड़ा है। सोमवार रक्षाबंधन के दिन सुबह सुबह– दो सगी बहनें सुनीता देवी (23) व पुनीता देवी (18) पुत्री सुरेश कुमार उर्फ गोबारी शौच के लिए घर से निकलीं थीं। घर से मात्र 200 मीटर की दूरी पर बह रही बिसुही नदी में एक दूसरे का हाथ दुपट्टे से बांधकर कूद गईं। घटना की सूचना पर एसडीएम यशवंत राव ,सीओ आरके सिंह, कोतवाल संतोष कुमार मिश्र व चौकी प्रभारी अरविंद कुमार मौके पर पहुंचे। एसडीआरएफ टीम भी बुलाई गयी। टीम के आने के पहले ग्रामीणों की मदद से दोनों लड़कियों के शव को नदी से निकाल लिया गया। सोमवार देर रात दोनों शवों को इक्टठा जेसीबी से खुदाई करके घुनाही घाट पर मिट्टी दे दी गयी।ीड़ित पिता सुरेश ने बताया कि दोनों बेटियां एक इंटर कालेज में पढती थी। सुनीता ने हाल ही में पढाई छोड़ी थी जबकि पुनीता कक्षा ग्यारह में थी। बड़ी बेटी की शादी पचपुतीजगतापुर कोल्हारगांव में हुई हैं। उसकी तबीयत खराब थी तो मझली बेटी सुनीता देवी बड़ी बेटी के घर गई थी। वापस आने पर बतायी कि जीजा भद्दे–भद्दे अपशब्द कहता है और धमकी देता है कि तुम्हारी शादी कहीं नहीं होने देंगे। नागपंचमी के दिन वहां से वापस आयी थी। आरोप है कि दामाद अशोक मेरी दोनों बेटियों को प्रताड़ित करता था।

बेटियों ने मुझे 18 तारीख को बताया था कि जीजा अपशब्द कहते हैं। कहते हैं कि तुम्हारी शादी नहीं होने देंगे। संतोष कुमार मिश्र, कोतवाल ने कहा कि युवतियों के पिता की लिखित शिकायत पर आरोपी अशोक कुमार पुत्र गंगू निवासी पचपुतीजगतापुर (कोल्हारगांव) के खिलाफ आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करने का मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है।

प्रेमी के दोनों हाथ गमछे से बांध दुपट्टे से गला कसकर मार डाला

संवाददाता–गोण्डा। प्रेमिका ने अपने ही प्रेमी को घर में बुलाकर पहले उसके ही गमछे से दोनों हाथ बांध दिया फिर दुपट्टे से गला कसकर मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद प्रेमी के ही लुंगी से शव बांधकर एक बोरे में भरकर सिल दिया और बोरा सिर पर लादकर तालाब में फेंक आई। पुलिस ने जब मृतक की काल डिटेल खंगाली तो महिला पर शक हुआ और पूछताछ में उसने प्रेमी की हत्या की बात कुबूल की। पुलिस ने प्रेमिका को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। एएसपी पूर्वी मनोज कुमार रावत ने सोमवार को हत्या का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी शरीफुन निशा पत्नी बुद्धू निवासनी कुकरिहा का काफी दिनों से गांव के ही कलामुद्दीन से अवैध संबंध चल रहा था। प्यार में पागल कलामुद्दीन ने अपना खेत बेचकर नकद रुपया और घरेलू सामान भी अपनी प्रेमिका को दे दिए। गांव के कई अन्य लोगों से प्रेमिका द्वारा बातचीत करने से दोनों के बीच झगड़ा हो गया। 15 अगस्त की रात कलामुद्दीन प्रेमिका के घर गया था। प्रेमिका शरीफुन निशा ने कलामुद्दीन को अपने घर से भगा दिया। कलामुद्दीन उसी रात फिर अपनी प्रेमिका के घर पहुंचा तो प्रेमिका शरीफुन निशा ने पहले उससे प्यार से बात की, विश्वास में लेकर उसके हाथ को उल्टा कर उसी के गमछे से बांध दिया, उसके बाद अपने दुपट्टे से गला कसकर उसकी हत्या कर दी। तीतगांव करुवापारा के पास स्थिति भरतानिया तालाब में शनिवार की देर शाम प्लास्टिक के बारे में भरी एक लाश मिली थी। शव की पहचान कलामुद्दीन उर्फ भज्जे (45) पुत्र स्व मोहम्मद अली निवासी कुकरिहा के रूप में हुई थी।

बेटी की तहरीर पर दर्ज हुआ था मुकदमा रू मृतक की बेटी शहनाज की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ कोतवाली इटियाथोक में हत्या व साक्ष्य छिपाने का मुकदमा दर्ज हुआ था।

अखिलेश यादव पर हमलावर हुए सीएम योगी, बोले– अयोध्या को बदनाम करने वाले दुष्कर्मियों के साथ खड़े

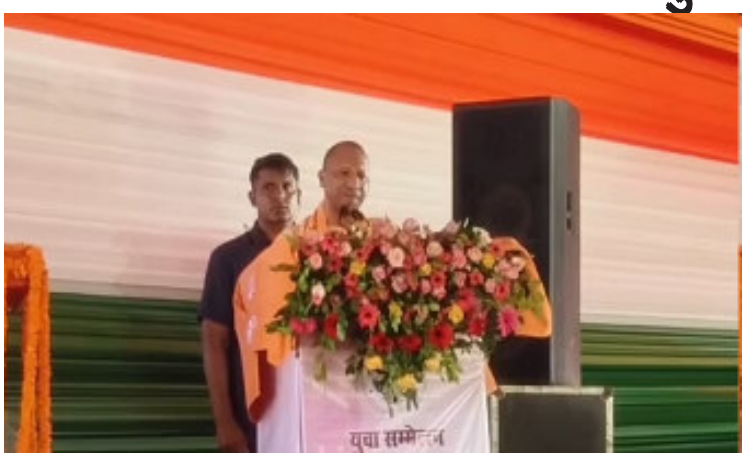

संवाददाता–अयोध्या। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिन्हें अयोध्या का विकास अच्छा नहीं लग रहा और जो इस नगरी से नफरत करते हैं, वे सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार कर रहे हैं। इसके लिए फेक न्यूज चलाई जा रही है। सीएम योगी आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में आयोजित वृहद रोजगार मेले को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अभी हाल ही में ऐसे लोगों ने ही यह दुष्प्रचार किया कि अयोध्या की 13000 एकड़ भूमि तीन लोगों को आवंटित कर दी गई जबकि ऐसा कोई आवंटन नहीं किया गया। इसी तरह धर्मपथ और रामपथ पर 3800 स्ट्रीट लाइट चोरी होने की सूचना प्रसारित की गई जबकि इन लाइटों को वेंडर ने लगाया ही नहीं था और पैसा निकालने के लिए साजिश रची थी। अब वेंडर शिकंजे में आ गया है। जल्द ही उसके आकाओं को भी शिकंजे में लिया जाएगा। अयोध्या को कटघरे में खड़ा करने के साथ ही साजिश के तहत बदनाम किया जा रहा है। यह वही लोग हैं जो दुष्कर्मियों के समर्थन में खड़े होते हैं। इन्हीं लोगों ने अयोध्या में निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवाई थी। हर दुष्कर्मी और अपराधी को निर्दोष साबित करना इन लोगों ने अपना लक्ष्य बना लिया है। इन लोगों के साथ सद्भाव से नहीं सख्ती से पेश आया जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अपने हाथों से 13 छात्र– छात्राओं को टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरण किया इसी कड़ी में 12 युवाओं को अपने हाथों से नियुक्ति पत्र प्रदान किया। सीएम योगी ने 78 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। समारोह में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, व्यावसायिक शिक्षा मंत्री कपिल देव अग्रवाल, स्वास्थ्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह, खेल मंत्री गिरीश यादव, खाद्य रसद राज्य मंत्री सतीश शर्मा और प्रमुख सचिव कार्मिक एम देवराज मौजूद रहे।

राबिनहुड आर्मी की बच्चियों को खेल में प्रोत्साहन का दिया भरोसा

संवाददाता–गोरखपुर। रॉबिनहुड आर्मी की तरफ से जरूरतमंदों के सहयोग में सामाजिक काम किए जाते हैं। बच्चों के बीच आर्मी की तरफ से एमएमएमयूटी में फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इस दौरान समापन के दिन ऑर्बिट के निदेशक अभिषेक अग्रवाल और सीओ कैंट अंशिका वर्मा को मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहीं। मैच के समापन के बाद परिसर में ही खिलाड़ियों और मुख्य अतिथियों के बीच एक दूसरे का परिचय कराया गया।

सीओ कैंट अंशिका वर्मा ने खिलाड़ी बच्चों का हौसला बढ़ाया। कहा, जज्बे से जीत और जिद से अपने सपने को पूरा किया जा सकता है। खिलाड़ियों में ये जज्बा और जोश देखकर उन्हें विश्वास है कि जल्द ही ये खिलाड़ी गोरखपुर के साथ अपनी आर्मी का नाम भी रौशन करेंगे। वहीं, अभिषेक अग्रवाल ने इस मौके पर महिला खिलाड़ियों के लिए वॉलीबॉल में किट दिए जाने की घोषणा की। कहा, खेल में ऐसे ही ये .युवा खिलाड़ी सामने आए और आगे बढ़ते जाएं तो एक दिन खेल में भी गोरखपुर का नाम देश–विदेश में परचम लहराएगा। उन्होंने इस मौके पर शहर के विभिन्न लोगों से अपील करते हुए कहा कि रॉबिनहुड आर्मी के साथ अधिक–अधिक लोग जुड़ें। इससे आर्मी की तरफ से जरूरतमंद बच्चों के लिए उपलब्ध करवाए जाने वाले अवसर और बेहतर हो सकेंगे।

बसपा ने मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर घोषित किया उम्मीदवार, राम गोपाल कोरी को बनाया प्रत्याशी

संवाददाता–अयोध्या। लोकसभा चुनाव के दौरान खाली हुई यूपी की 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। उपचुनाव की तारीखों का अभी भले ही घोषणा न हुई हो लेकिन सियासी दल चुनाव को लेकर तैयारियों में जुट गए हैं। बसपा ने तो उम्मीदवारों की घोषणा भी शुरू कर दी है। बसपा प्रमुख मायावती ने रविवार को अयोध्या जिले की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर प्रत्याशी उतार दिया है। एक सप्ताह पहले दो सीटों पर बसपा पहले ही अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर चुकी है। मिल्कीपुर सीट से बसपा ने रामगोपाल कोरी पर भरोसा जताया है। रामगोपाल कोरी ने 2017 में भी बसपा की टिकट से चुनाव लड़ा था, लेकिन उस समय रामगोपाल तीसरे नंबर पर रहे थे। बतादें कि 2022 के विधानसभा चुनाव में ये सीट सपा के खाते में गई थी। इस सीट से सपा के अवधेश प्रसाद विधायक थे, लेकिन अयोध्या लोकसभा सीट से चुनाव जीतने के बाद उन्होंने विधायकी से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद से ये सीट खाली हो गई।

यूपी में होने वाली 10 में से तीन विधानसभा सीटों पर बसपा अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर चुकी है। पिछले सप्ताह बसपा सुप्रीमो ने पार्टी कार्यालय पर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों की समीक्षा की थी। सभी 10 सीटों के लिए उम्मीदवारों के तैयार किए गए पैनल पर चर्चा हुई थी। जोनल प्रभारियों से और योग्य व कर्मठ उम्मीदवारों के नाम मांगे। इसी दौरान फूलपुर से शिव बरन पासी और मझवा सीट से दीपू तिवारी की उम्मीदवारी पर सहमति दे दी थी। उन्होंने कहा था कि उपचुनाव के लिए भले ही तारीख की अधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन सरगर्मी लगातार बढ़ रही है। बीते शनिवार को हुई बसपा की बैठक में मायावती यूपी की सभी सीटों पर प्रत्याशी उतारने का ऐलान कर चुकी हैं। मायावती के इस ऐलान के बाद से ही सपा–कांग्रेस और भाजपा की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने यूपी में 10 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव को प्रतिष्ठा का सवाल बनाते हुए दमदारी से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। इस चुनाव को फतेह करने के लिए बसपा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आरक्षण और नजूल भूमि वापस लेने के फैसले को मुद्दा बनाते हुए विरोधियों की पोल खोलेगी। इसके लिए पार्टी कार्यकर्ता घर–घर जाएंगे और मायावती के वक्तव्य की प्रतियां बांटेंगे। बताएंगे कि कैसे दूसरे दल आरक्षण को लेकर उनको भ्रमित कर रहे हैं।

बसपा आमतौर पर उपचुनाव नहीं लड़ती है, लेकिन अब जब मायावती ने ये ऐलान किया है तो कई जानकारों का मानना है कि बसपा का ये फैसला कहीं सपा–कांग्रेस तो कहीं भाजपा का खेल बिगाड़ सकता है। हालांकि पिछले दो चुनावों (2024 लोकसभा और 2022 विधानसभा में) में यूपी में बसपा का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा है। बसपा के लिए आने वाले उपचुनाव में भी जमीनी स्तर पर चुनौतियां कम नहीं हैं। इसके बाद भी बसपा के पास उसके इतने परंपरागत वोटर तो हैं ही कि कई सीटों पर असर डाल सकते हैं। उधर, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार बसपा को भाजपा की बी टीम बता रहे हैं। उपचुनाव की सभी सीटें लड़ने के मायावती के ऐलान के बाद भी सपा नेताओं ने अपनी प्रतिक्रियाओं में ऐसे आरोप लगाए।

पूर्वोत्तर रेलवे के विकास के लिए मंत्रालय ने दिया 6470.20 करोड़ रुपय

संवाददाता–गोरखपुर। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में मिले बजट से पूर्वोत्तर रेलवे में चल रहे विकास कार्यों की गति में न सिर्फ तेजी आएगी, बल्कि समय से निर्माण कार्य भी पूरे होंगे। यात्री सुविधाओं का विस्तार होगा।पूर्वोत्तर रेलवे का विकास 6470.20 करोड़ रुपये से होगा। पूर्वोत्तर रेलवे में पड़ने वाले पूर्वोत्तर रेलवे, उत्तर रेलवे और उत्तर मध्य रेलवे के विकास के लिए भी रेल मंत्रालय ने रिकार्ड 19, 848 करोड़ रुपये का प्रविधान किया है।बजट 2024–25 में पूर्वोत्तर रेलवे में चल रही नई रेल लाइनों के विस्तार, दोहरीकरण, तीसरी रेल लाइन और आमान परिवर्तन (छोटी से बड़ी लाइन) के लिए पर्याप्त धन मिला है। सहजनवां–दोहरीघाट, आनंदनगर–घुघली और खलीलाबाद–बहराइच नई रेल लाइन के निर्माण में तेजी आएगी। गोरखपुर कैंट–वाल्मीकिनगर और भटनी–औड़िहार रेलमार्ग का समय से दोहरीकरण पूरा होगा। कैंट–वाल्मीकिनगर का दोहरीकरण आरंभ हो चुका है। भटनी–औड़िहार का कार्य प्रगति पर है।

गोरखपुर के रास्ते कुसम्ही से डोमिनगढ़ के बीच तीसरी रेल लाइन (थर्ड लाइन) भी दिसंबर 2024 तक बिछ जाएगी। चल रहे इन निर्माण कार्यों को गति मिलेगी। ट्रेनों की रफ्तार 110 से 130 किमी प्रति घंटे बढ़ाने के लिए रेल लाइन बदली जा रही हैं। आटोमेटिक ब्लाक सिग्नल सिस्टम लगाए जा रहे हैं। इसके लिए भी बजट मिला है। दुर्घटनाओं को पूरी तरह रोकने तथा आमजन की सुविधा के लिए समपार फाटकों पर रोड ओवरब्रिज (आरओबी) और रोड अंडरब्रिज (आरयूबी) बनाए जा रहे हैं। इसके निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए 441.70 करोड़ का प्रविधान किया गया है।

नाबालिग को कोचिंग पढ़ाते–पढ़ाते उसे लेकर मौलवी हुआ फरार

संवाददाता–गोरखपुर। पर ट्यूशन पढ़ाने आने वाला मौलवी ही नाबालिग को लेकर फरार हो गया।मौलवी ने किशोरी को घर पर तालीम देने के बहाने फरार हो गया। कई दिनों तक तलाश के बाद भी मौलवी और बच्ची नहीं मिले तो किशोरी के पिता ने कोतवाली थाने में केस दर्ज कराया है। पुलिस केस दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुटी है। शहनवाज नाम का एक युवक रेती रोड पर स्थित मस्जिद पर नमाज पढ़ाता था। यही पर उसकी मुलाकात लड़की के पिता से हो गई। लड़की के ट्यूशन के लिए पिता ने उससे बात की और फिर घर पर तालीम देने के लिए आने लगा। छह महीने तक घर पढ़ाई के लिए आने के दौरान ही उसने नाबालिग लड़की को अपनी बातों में फंसा लिया। एक दिन अचानक वह लड़की को लेकर घर से लापता हो गया। मौलवी और लड़की दोनों के गायब होने के बाद परिजनों का शक यकीन में बदल गया और फिर वह कोतवाली थाने पहुंचकर आरोपी पर केस दर्ज करा दिए। पिता का कहना है कि बेटी से न कोई संपर्क हो रहा है, न ही शातिर बदमाश से। बेटी के साथ कोई इसके पहले पुलिस उसे सुरक्षित बरामद करे।

बताया जा रहा है कि वह पिछले छह महीने से घर पर आ रहा था, लेकिन उसने ऐसी शर्मनाक हरकत कर दी। इस घटना को लेकर परिवार वालों में जबरदस्त गुस्सा है। वह पुलिस के पास बड़ी कार्रवाई करने के लिए दौड़ रहे हैं। एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर कोतवाली थाने में केस दर्ज कर लिया गया है।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक, शक्ति शंकर द्वारा फाईन आफसेट प्रिंटर्स मदरसा हुसैनिया बिल्डिंग बक्शीपुर, जनपद–गोरखपुर से मुद्रित कराकर, मुहल्ला–द्वितीय तल पुष्पांजलि काम्प्लेक्स शाही मार्केट, गोलघर, जनपद–गोरखपुर से प्रकाशित।
प्रधान संपादक :
शक्ति शंकर
मो नं.
7233999001
सभी विवादों का न्याय क्षेत्र गोरखपुर न्यायालय होगा।